



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1277-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के तहत आपराधिक अपील संख्या - 212/2025

राम प्रसाद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: नरेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

आपराधिक प्रकीर्ण विलंब माफी आवेदन संख्या 01/2025 पर आदेश

- वर्तमान अपील अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, हाथरस द्वारा मामला अपराध संख्या 890/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 185 एवं मामला अपराध संख्या 890/2014 के तहत धारा 364 और 308 भा.द.सं., पुलिस स्टेशन सिकंदराऊ, जिला हाथरस के तहत बरी करने के निर्णय के विरुद्ध 45 दिनों की विलंब के पश्चात दायर की गई है।
- सूचनादाता-अपीलकर्ता ने तत्काल विलंब माफी आवेदन दायर किया है।
- शुरुआत में, इस न्यायालय द्वारा एक प्रश्न किया गया था कि विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है।
- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने काफी हद तक स्वीकार किया कि कानून के तहत आवश्यक देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है, हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की खराब

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वित्तीय पृष्ठभूमि के कारण देरी हुई है क्योंकि वह एक गरीब मजदूर है, जिसके कारण, वह वर्तमान अपील दायर करने के लिए पर्याप्त धन का प्रबंधन नहीं कर सका।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि अनजाने में, शपथपत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जब अपीलकर्ता द्वारा धन की व्यवस्था की गई थी और जब इसे वर्तमान अपील दायर करने के लिए उसके अधिवक्ता को सौंप दिया गया था, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि अपीलकर्ता की खराब वित्तीय पृष्ठभूमि के आधार पर, देरी हो सकती है, क्षमा किया जाए।

6. विलंब माफी आवेदन के साथ शपथपत्र में वर्तमान अपील दायर करने में देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है, हालांकि, वर्तमान अपील केवल 45 दिनों की देरी से दायर की गई है। स्थापित कानून के आलोक में एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कि किसी भी योग्य मामले को केवल कुछ तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता की खराब वित्तीय पृष्ठभूमि को देखते हुए, वर्तमान अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

7. कार्यालय अपील को नियमित संख्या आवंटित करेगा।

अपील के ज्ञापन पर आदेश

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विपरीत पक्ष के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. इस आपराधिक अपील में चुनौती अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, हाथरस द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 185/2025 में पारित बरी करने के निर्णय को चुनौती दी गई है, जो मामला अपराध संख्या 890/2014 में धारा 364 और 308 भा.द.सं., पुलिस स्टेशन सिकंदराऊ, जिला हाथरस से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत आरोपी विरोधी पक्ष विनोद को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से निचली अदालत ने बरी कर दिया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचनादाता-अपीलकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन सिकंदराऊ में दिनांक 29.10.2014 की एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसका बेटा अरुण कुमार, जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी, जो दिनांक 29.10.2014 को शाम लगभग 4:00 बजे अपने घर से खेलने के लिए बाहर गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। उन्होंने हर जगह तलाशी ली है, लेकिन उनका बेटा अभी भी लापता है। सूचनादाता-अपीलकर्ता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की उक्त लिखित रिपोर्ट ((प्रदर्श क -1) पर, 29.10.2014 को संबंधित थाना में भा.द.सं. की धारा 363 के तहत मामला अपराध संख्या 890/2014 के रूप में एक एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। इसके बाद, एक दूसरी लिखित शिकायत (प्रदर्श क-2) दिनांक 09.12.2014 को संबंधित पुलिस स्टेशन में सूचनादाता-अपीलकर्ता द्वारा फिर से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसका बेटा 29.10.2014 को शाम 4:00 बजे से लापता था। 30.10.2014 को सुबह करीब 11:00 बजे सैयद बाबा के घर के पास खेतों में काम कर रहे लोगों ने उनके बेटे को कुएं में पड़ा पाया। उन्होंने उसके पड़ोस को सूचित किया और सभी लोग मौके पर पहुंचे, उसके बेटे को कुएं से बाहर निकाला गया, जो बेहोश था और गंभीर रूप से घायल था। उसे अस्पताल ले जाया गया। आरोपी-प्रतिपक्षी को यह पता चलने पर कि उसका बेटा होश में आ गया है, अपने घर से भाग गया और इसलिए, उसे संदेह है कि उसके बेटे का अपहरण आरोपी-विरोधी पक्ष विनोद ने किया था। उनके बेटे को पहले 22.10.2014 को शाम लगभग 6:00 बजे विनोद द्वारा नदी में ले जाया गया था और उस समय, उनकी पत्नी नदी के किनारे से घास ला रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है? इस पर उनके बेटे अरुण ने उन्हें बताया कि आरोपी प्रतिपक्षी विनोद उन्हें लेकर आए हैं और उन्हें नदी पार करने के लिए कहा है। पत्नी ने विनोद से पूछा कि वह मेरे बेटे को वहां क्यों लाए हैं, जिस पर विनोद ने उसे बताया कि उसका मोबाइल गिर गया है, इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि यह छोटा बच्चा आपका मोबाइल कैसे ढूँढेगा? पत्नी ने विनोद से कहा कि वह अपने बेटे को दोबारा वहां न लाए। उस दिन से, सूचनादाता-अपीलकर्ता को संदेह था कि उसके बेटे का अपहरण आरोपी-प्रतिपक्षी द्वारा किया गया था। अपीलकर्ता की दूसरी लिखित शिकायत (प्रदर्श क-2) पर, उपरोक्त मामले के अपराध को भा.द.सं. की धारा 363 से धारा 364 और 308 भा.द.सं. में बदल दिया गया था।

4. जांच पूरी होने के बाद विरोधी पक्ष विनोद के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 364 और 308 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद, उस पर संज्ञान लिया गया और मामले को सत्र न्यायालय में सौंप दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी विनोद के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 364 और 308 के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि, आरोपी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 को सूचनादाता राम प्रसाद (बच्चे अरुण के पिता), पीडब्लू-2 विमला देवी, (बच्चे अरुण की मां), पीडब्लू-3 अरुण कुमार (पीड़ित), पीडब्लू-4 डॉ. संजय भार्गव, पीडब्ल्यू-5 रणवीर सिंह (जांच अधिकारी) और पीडब्लू-6 रणवीर सिंह को जोड़ा। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य दिए हैं और अभियोजन पक्ष के 8 कागजात, अर्थात्, पहली लिखित रिपोर्ट (प्रथम तहरीर) दिनांक 29.10.2014 को प्रदर्शक-1 के रूप में, दूसरी लिखित रिपोर्ट (दूसरी तहरीर) दिनांक 09.12.2024 को प्रदर्शक -2 के रूप में, चोट रिपोर्ट प्रदर्शक -3 के रूप में, नक्सा नजरी प्रदर्शक -4 के रूप में, घटना का स्थान प्रदर्शक -5, चार्ज-शीट प्रदर्शक -6 के रूप में, जीडी प्रवेश प्रदर्शक -7 के रूप में और चिक एफआईआर प्रदर्शक -8 के रूप में भी साबित किए हैं।

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सभी प्रतिकूल/आपत्तिजनक परिस्थितियों का खुलासा सीआरपीसी की धारा 313 के अधिदेश के अनुसार घटना के उसके संस्करण के लिए प्रश्न उत्तर प्रपत्र में अभियुक्त को किया गया था। अभियुक्त ने बार-बार यह कहकर उसके सामने रखे गए सभी प्रतिकूल/आपत्तिजनक तथ्यों से इनकार किया कि यह गलत है या उसे झूठा फंसाया गया है या अभियोजन पक्ष का मामला झूठा है या अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठी गवाही दी है।

7. दिनांक 01.08.2025 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, नीचे की अदालत ने आरोपी-विरोधी पक्ष को धारा 364 और 308 भा.द.सं. के तहत आरोप से बरी कर दिया है। इस प्रकार, नीचे के न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, वर्तमान अपील को सूचनादाता-अपीलकर्ता द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

8. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य-विरोधी पक्ष के लिए विद्वान एजीए को भी सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. बरी होने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि यदि दो विचार संभव हैं, एक बरी करने का समर्थन करता है और दूसरा दोषसिद्धि का संकेत देता है, तो उच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में, नीचे के न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश को उलट नहीं देना चाहिए। इस संबंध में **चंद्रप्पा और**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 (4) एससीसी 415: एआईआर 2007 एससीसी (एसयूपीपी) 111

में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ के बारे में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

(1) एक अपीलीय न्यायालय के पास उन सबूतों की समीक्षा, पुनः मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है;

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं रखती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर नहीं रखता है;

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियां, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियां', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियां', आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। इस तरह की वाक्यांशावली 'भाषा के उत्कर्ष' की प्रकृति में अधिक हैं जो सबूतों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए न्यायालय की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देती हैं।

(4) तथापि, अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसके पास उपलब्ध निर्दोषता की धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह कानून की एक सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरे, अभियुक्त ने अपनी बरी कर लेने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा और मजबूत, पुनः पुष्टि और स्वीकृत किया जाता है।

(5) यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज बरी करने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 के मामले में शीर्ष न्यायालय को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए निम्नानुसार अवधारित किया गया है: -

"39. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि अभियुक्त के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे का प्रयोग निम्नलिखित सिद्धांतों के चार कोनों के भीतर किया जाना चाहिए: -

(ए) यह कि बरी करने का निर्णय पेटेंट विकृति से ग्रस्त है;

(ख) यह अभिलेख पर भौतिक साक्ष्य पर विचार करने के लिए गलत पाठ/चूक पर आधारित है;

(ग) कोई दो युक्तिसंगत विचार संभव नहीं हैं और केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप दृष्टिकोण ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से संभव है।

40. अपीलीय न्यायालय को, बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए, उपरोक्त कारकों पर प्रासंगिक निष्कर्षों को दर्ज करना होगा यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए बरी होने के फैसले को उलटने के लिए इच्छुक है।

11. उपर्युक्त निर्णयों में यह भी देखा गया है कि एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसके लिए निर्दोषता की धारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह कानून की एक सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरे, अभियुक्त ने अपनी बरी कर लेने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को नीचे के न्यायालय द्वारा और मजबूत, पुनः पुष्टि और मजबूत किया जाता है। यह भी देखा गया है कि अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह निष्कर्ष निकलता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया जा सकने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाला एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।

12. गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 10 एससीसी 636 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बरी होने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। आगे यह धारित किया गया कि यह विकल्प उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध है कि वह नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा प्राप्त सबूतों और निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन कर सके। हालाँकि, यह उन मामलों तक सीमित है जहां नीचे दिए गए न्यायालय का निर्णय विकृत था। इस न्यायालय ने यह घोषणा की कि विधि के अनुसार "विकृत" शब्द, का अर्थ "साक्ष्य के वजन के खिलाफ" समझा गया है। यदि दो विचार हैं और नीचे दिए गए न्यायालय ने केवल इसलिए एक विचार लिया है क्योंकि एक और दृष्टिकोण प्रशंसनीय है, तो अपीलीय न्यायालय बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने में उचित नहीं होगा।

13. उपर्युक्त सुस्थापित विधिक स्थिति के आलोक में आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करते समय निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं: -

i. सूचनादाता का बेटा अरुण 29.10.2014 को शाम 4:00 बजे से लापता हो गया।

ii. सूचनादाता-अपीलकर्ता ने 29.10.2014 को अपने बेटे के लापता होने के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन में भा.द.सं. की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

iii. जब पहली लिखित सूचना/तहरीर (प्रदर्श क-1) सूचनादाता द्वारा पेश की गई थी, तो उसे आरोपी-प्रतिपक्षी विनोद पर कोई संदेह नहीं था। सूचनादाता का बेटा अरुण 30.10.2014 को सुबह लगभग 11:00 बजे एक कुएं में पड़ा पाया गया था।

iv. सूचनादाता-अपीलकर्ता ने दिनांक 09.12.2014 को हुई घटना के संबंध में संदेह के आधार पर आरोपी-प्रतिपक्षी का नाम देते हुए दूसरी लिखित सूचना/तहरीर (प्रदर्श क-2) दिनांक 09.12.2014 को स्थानांतरित किया, जिसमें उसके बेटे अरुण को अभियुक्त-प्रतिपक्षी विनोद द्वारा नदी में ले जाया गया था। सूचनादाता की पत्नी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने आरोपी विरोधी पक्ष विनोद पर आपत्ति जताई और विनोद से कहा कि वह अपने बेटे को फिर से वहां न लाए।

(v) दूसरी सूचना/तहरीर (प्रदर्श क-2) को प्रथम सूचना प्रस्तुत करने के एक महीने और दस दिनों के बाद स्थानांतरित किया गया था।

vi. सूचनादाता-अपीलकर्ता के रूप में राम प्रसाद के बयान के अनुसार पीडब्लू-1 और डॉ. संजय भार्गव को पीडब्लू-4 के रूप में, सूचनादाता के बेटे को 20.11.2014 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

vii. द्वितीय सूचनादाता/तहरीर (प्रदर्श क-2) में, सूचनादाता-अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसकी पत्नी ने उसे सूचित किया था कि उसके बेटे को 22.10.2014 को आरोपी विरोधी पक्ष द्वारा नदी में ले जाने के बारे में सूचित किया गया था, जहां उसकी पत्नी ने विशेष रूप से आरोपी-प्रतिपक्षी विनोद से अपने बेटे को फिर से वहां नहीं लाने के लिए कहा था और यही कारण है कि उसे अपने बेटे के अपहरण में आरोपी-विरोधी पक्ष विनोद की संलिप्तता का संदेह था। सूचनादाता पीडब्लू-1 और उसकी पत्नी विमला देवी पीडब्लू-2 का पति-पत्नी के रूप में संबंध विश्वास पर आधारित है। यदि सूचनादाता की पत्नी को अभियुक्त-प्रतिपक्षी की संलिप्तता का संदेह था, तो उसे 29.10.2014 को अपने पति को सूचित करना चाहिए था और आरोपी-विरोधी पक्ष का नाम पहली तहरीर (प्रदर्श क-1) में शामिल किया जा सकता था।

viii. इसके अलावा, दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2) में भी, सूचनादाता ने केवल 22.10.2014 की घटना के आधार पर अपने संदेह का उल्लेख किया है, जो घटना उसकी पत्नी ने देखी थी।

ix. पीडब्लू-1 राम प्रसाद और पीडब्लू-2 विमला देवी अपहरण की घटना या अंतिम बार देखे गए घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं।

x. सूचनादाता के बेटे अरुण को 20.11.2014 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरुण को वास्तव में होश कब

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आया। चूंकि उसे 20.11.2014 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, इसलिए, उसने अपने माता-पिता को उस व्यक्ति के नाम के बारे में सूचित किया होगा, जिसने उसके साथ कथित कार्य किया था, या तो होश में आने पर या उसके डिस्चार्ज होने पर, लेकिन दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2) स्पष्ट है कि अरुण ने अपने माता-पिता में से किसी को भी ऐसा नहीं बताया था।

xi. विचारण न्यायालय ने पाया कि दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2) स्वतंत्र दिमाग से नहीं लिखी गई थी, बल्कि विधिक सलाहकार से सलाह के पश्चात लिखी गई थी।

xii. अभियोजन पक्ष कथित अपराध करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी भी मकसद को साबित करने में विफल रहा है।

xiii. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, दो घटनाएं हुईं, पहली 20.10.2014 की और दूसरी 29.10.2014 की। हालांकि, अरुण पीडब्लू-3 के बयान के अनुसार, दोनों घटनाएं, जो उसके साथ हुई थीं, यानी नदी के पास हुई घटना और नदी से वापस लौटने के बाद उसे कुएं में फेंकने की घटना, एक ही दिन की थी। यदि पीडब्लू-3 अरुण के बयान पर विश्वास किया जाए, तो दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई थीं और यदि ऐसा था, तो सूचनादाता/अपीलकर्ता ने 29.10.2014 को तुरंत आरोपी-प्रतिपक्षी के खिलाफ नामित प्राथमिकी दर्ज की होगी। चूंकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं था, इसलिए एक ही दिन दो कथित घटनाएं नहीं हो सकती हैं।

xiv. उपरोक्त पृष्ठभूमि पर, पीडब्लू-2 विमला देवी ने आरोपी-विरोधी पक्ष विनोद से कहा कि वह 22.10.2024 को अपने बेटे को फिर कभी अपने साथ नहीं ले गई, लेकिन वह अपने नाबालिग बेटे को मौके से नहीं ले गई, बल्कि अपने बेटे को विपरीत पक्ष विनोद के साथ छोड़ दिया, जो एक संदिग्ध परिस्थिति है।

xv. पहली और दूसरी तहरीर (यानी प्रदर्श क-1 और प्रदर्श क-2) में बताई गई जानकारी एक दूसरे के विपरीत है।

xvi. अभियोजन पक्ष दूसरे तहरीर यानी प्रदर्श क-2 में विरोधी पक्ष के आरोपी के नाम में अत्यधिक देरी की व्याख्या करने में बुरी तरह विफल रहा है, इसके अलावा,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

20.11.2014 को घायल अरुण को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी अभियुक्त का नाम लेने में अत्यधिक विलंब हुआ है और अभियोजन पक्ष द्वारा इस देरी को भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

xvii. अभियोजन पक्ष की कहानी और पीडब्लू-1 राम प्रसाद और पीडब्लू-2 विमला देवी के बयानों के अनुसार, उनके बेटे को उनकी उपस्थिति में कुएं से बाहर निकाला गया था और इससे पहले, उन्हें सूचित किया गया था कि उनका बेटा अरुण एक कुएं में पड़ा हुआ पाया गया है। अरुण पीडब्लू-3 ने अपने बयान में कहा है कि उसे बोरे में डालकर कुएं में फेंक दिया गया था। पीडब्लू -3 अरुण ने आगे कहा कि वह उस समय बेहोश था। इस पृष्ठभूमि में, किसी के लिए किसी को पहचानना असंभव था, जिसे बेहोशी की अवस्था में बोरे में रखा गया है, वह भी एक कुएं में।

xviii. उस व्यक्ति का नाम, जिसने अपीलकर्ता को अपने बेटे के कुएं में पड़े पाए जाने के बारे में सूचित किया था, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में नहीं आया है।

xix. उपरोक्त तथ्य अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और इसने वास्तव में इस कहानी को नष्ट कर दिया।

xx. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि आरोपी विनोद ने सूचनादाता के बेटे का अपहरण कर लिया था, उसकी मौत का कारण बनने के इरादे से और उसे चोट पहुंचाने के बाद एक बोरे में डाल दिया गया था और उसके बाद कुएं में फेंक दिया गया था।

14. विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त उपरोक्त निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में सक्षम नहीं है, रिकॉर्ड पर सबूतों के आलोक में पहली तहरीर (प्रदर्श क-1) और दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2) में लगाए गए आरोपों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। हमारे द्वारा जांच करने पर, उक्त निष्कर्षों और उपरोक्त कारणों से, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आलोक में, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया गया है, हम ऐसे किसी भी तथ्य पर नहीं आ सके, जिसके आधार पर, किसी भी निष्कर्ष को आरोप लगाने वाली धाराओं को विकृत या गलत कहा जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. दिनांक 29.10.2014 को शाम 4:00 बजे से सूचनादाता-अपीलकर्ता के बेटे अरुण के लापता होने के संबंध में पहली तहरीर (प्रदर्श क-1) उसी दिन सूचनादाता-अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी और उक्त एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं था। सूचनादाता-अपीलकर्ता ने 17.12.2014 को दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2) का रुख किया, जिसके तहत भा.द.सं. की धारा 363 के तहत दर्ज मामले को भा.द.सं. की धारा 364 और 308 के तहत बदल दिया गया। दूसरे तहरीर (प्रदर्श क-2) में सूचनादाता-अपीलकर्ता ने 22.10.2014 को हुई एक पिछली घटना के संदेह में अभियुक्त-विरोधी पक्ष विनोद को आरोपी के रूप में नामित किया, साथ ही इस संदेह पर कि आरोपी-प्रतिपक्षी अरुण को होश में आने का पता चलने के बाद अपने घर से भाग गया। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सूचनादाता-अपीलकर्ता अरुण का बेटा 22.10.2014 को शाम लगभग 6:00 बजे सूचनादाता की पत्नी द्वारा नदी के पास अभियुक्त-विरोधी पक्ष विनोद के साथ पाया गया था। उसने मौके पर ही आरोपी पक्ष विनोद से कहा था कि वह उसके बेटे को फिर कभी न लाए। दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस घटना के कारण, सूचनादाता-अपीलकर्ता को उस दिन से संदेह है कि उसके बेटे अरुण का अपहरण अभियुक्त-विरोधी पक्ष विनोद ने किया था।

16. यह बहुत आश्चर्य की बात है कि दिनांक 22.10.2014 की कथित घटना के बाद भी, सूचनादाता-अपीलकर्ता ने 29.10.2014 से पहली तहरीर (प्रदर्श क-1) में आरोपी का नाम नहीं लिया, जब उसका बेटा अरुण लापता हो गया था। यह काफी संभव और स्वाभाविक है कि उसकी पत्नी ने उसे 22.10.2014 की घटना के बारे में बताया होगा और उस स्थिति में, उसकी पत्नी से यह जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद पहली तहरीर (प्रदर्श क-1) में आरोपी का नाम लेने की पूरी संभावना थी। इस बीच, सूचनादाता के बेटे अरुण को 30.10.2014 को बरामद किया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि अरुण (सूचनादाता का बेटा) बेहोश था, जिसे 20.11.2014 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि अपहृत अरुण वास्तव में होश में आने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई होगी, लेकिन उसे पूरा इलाज मिलने के बाद और पूरी तरह से होश में आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई होगी। जब भी अरुण को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले या छुट्टी मिलने की तारीख पर होश आता है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक और संभव है कि उसने अपने माता-पिता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को उस व्यक्ति के बारे में सूचित किया होगा जिसने उसका अपहरण किया था। लेकिन वर्तमान मामले में, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि पीड़ित अरुण ने अपने माता-पिता को आरोपी-विरोधी पक्ष विनोद के बारे में सूचित किया है, यही कारण है कि विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों में सही पाया है कि दूसरी तहरीर का नाम आरोपी-प्रतिपक्षी को स्वतंत्र विवेक से नहीं लिखा गया है, बल्कि विधिक सलाहकार की सलाह पर लिखा गया है, जिसे आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ-25 में उपयुक्त रूप से दर्ज किया गया है।

17. इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से आक्षेपित फैसले के पैराग्राफ -39 में दर्ज किया है कि यदि अभियोजन की कहानी पर विश्वास किया जाए, तो अरुण पीडब्लू -3 को एक कुएं में फेंक दिया गया था और उसे कुएं में फेंकने से पहले, उसे एक बोरी में डाल दिया गया था। यह स्वीकार किया गया है कि वह बेहोश था और उसे उसके माता-पिता की उपस्थिति में बाहर निकाला गया था। इस पृष्ठभूमि में, सूचनादाता-अपीलकर्ता को अपने बेटे से पहले जानकारी कैसे मिली, यह एक संदिग्ध परिस्थिति है। क्योंकि एक व्यक्ति, जो बेहोश है और बोरे में डाल दिया जाता है और उसके बाद कुएं में फेंक दिया जाता है, उसे बोरी खोलने से पहले कुएं के बाहर खड़े व्यक्ति द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पैराग्राफ-39 में दर्ज किए गए निष्कर्ष वैध हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की उचित अवलोकन के बाद दर्ज किए जाते हैं।

18. आश्चर्यजनक रूप से, दूसरी तहरीर (प्रदर्श क-2), जिसे दिनांक 17.12.2014 को स्थानांतरित किया गया है, में अरुण से प्राप्त किसी भी जानकारी के बारे में उल्लेख नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, आरोपी-प्रतिपक्षी विनोद का नाम लेने में 50 दिनों की अत्यधिक देरी हो रही है। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि कथित अपहृत अरुण पीडब्लू -3 ने अपने माता-पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज की तारीख, यानी 20.11.2014 को उसके साथ उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराध के बारे में सूचित किया होगा जिसने किया था, तब भी, अभियुक्त-विरोधी पक्ष का नाम लेने में 27 दिनों की अत्यधिक देरी होती है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त-विरोधी पक्ष विनोद का नाम लेने में देरी की व्याख्या करने में विफल रहा है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है।

19. पीड़ित अरुण पीडब्लू-3 के बयान के अनुसार, पूरी घटना 22.10.2014 को हुई थी, जबकि पीडब्लू-1 राम प्रसाद और पीडब्लू-2 विमला देवी, यानी पीड़िता के पिता और मां के बयानों के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार, दो अलग-अलग घटनाएं थीं, पहली घटना 22.10.2014 की थी और दूसरी घटना 29.10.2014 की थी। इसलिए, इन गवाहों के बयानों में एक तीव्र विरोधाभास है, जो अभियोजन की कहानी पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न उठाता है, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ-37 में सही ढंग से दर्ज किया है कि यदि उपरोक्त दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई हैं, तो उस स्थिति में, सूचनादाता को आरोपी के खिलाफ नामित प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। हालांकि, एफआईआर में आरोपी का नाम लेने में सूचनादाता की विफलता यह साबित करती है कि उपरोक्त दो घटनाएं एक ही दिन एक ही क्रम में नहीं हुईं। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है।

20. ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, हमें निर्णय में कोई विकृति नहीं मिलती है ताकि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। नीचे न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित सराहना का परिणाम है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई गलत पाठ या चूक नहीं बताई जा सकी। अदालत ने किसी भी भौतिक साक्ष्य को गलत नहीं समझा है। हम रिकॉर्ड से ऐसा कोई तथ्य एकत्र नहीं कर सके ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के वजन के खिलाफ है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप दृष्टिकोण ही संभव है। इसलिए, हमें धारा 413 बीएनएसएस के तहत दायर वर्तमान अपील पर विचार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है, जो परिणामस्वरूप विफल हो जाता है और तदनुसार **खारिज** कर दिया जाता है।

21. वर्तमान आपराधिक अपील दायर करने में देरी को माफ करने के बाद वर्तमान आपराधिक अपील को दाखिल स्तर में खारिज कर दिया गया है और कार्यालय को पहले ही इस आपराधिक अपील के लिए नियमित संख्या आवंटित करने का निर्देश दिया गया है, जिसे अभिलेख के प्रयोजन के लिए आवंटित किया जाएगा।

22. अभिलेखित किया जाए।

6 जनवरी, 2026

मोनिका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।